हांगकांग में है नीरव मोदी, सरकार ने किया गिरफ्तारी का अनुरोध

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (ए)। पीएनबी लोन घोटाले में वांछित नीरव मोदी हांगकांग में है। विदेश मंत्रालय ने हांगकांग प्रशासन से उसकी अंतरिम गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, मंत्रालय ने चीनी जनवादी गणराज्य की हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार से नीरव दीपक मोदी की अंतरिम गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। इस संबंध में 23 मार्च, 2018 को अनुरोध पत्र उन्हें सौंप दिया गया। वीके सिंह ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे। सीबीआइ की ओर से उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया था। विदेश मंत्रालय ने 16 फरवरी को दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था। लेकिन वे (नीरव मोदी और मेहुल चोकसी) निश्चित समय सीमा में जवाब देने में असफल रहे इसलिए 23 फरवरी, 2018 को उनके पासपोर्ट रद कर दिए गए थे।

बैजल लंबित फाइलों को लेकर सच्चाई छुपा रहे हैं : आप सरकार

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (ए)। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल पर 'प्रगति रिपोर्ट' को लेकर दिये गए वक्तव्य पर गुरुवार को हमला करते हुए कहा कि वह अपने कार्यालय में लंबित फाइलों को लेकर वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पेश की गई 'आउटकम रिपोर्ट (प्रगति रिपोर्ट)'को लेकर बैजल के कार्यालय की ओर से जारी एक वक्तव्य को लेकर इस आशय की प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैजल के कार्यालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया था कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में उप राज्यपाल के कार्यालय ने 10 हजार से अधिक फाइलें प्राप्त की हैं। आप सरकार ने अपने वक्तव्य में आरोप लगाया कि उप राज्यपाल कार्यालय ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके कार्यालय ने जो फाइलें प्राप्त कीं उनमें अधिकांश पुलिस, डीडीए और अन्य सेवाओं से जुड़े तबादलों की फाइलें शामिल थीं। वक्तव्य में कहा गया, वास्तव में एलजी के कार्यालय में प्राप्त फाइलों में से 50 प्रतिशत पैरोल फाइल हैं। इसलिए, तीन प्रतिशत संया देकर, उप राज्यपाल का कार्यालय अपने कार्यालय द्वारा लंबित फाइलों की वास्तविकता को ढंकने की कोशिश कर रहा है।

हवाई सुरक्षा मानकों की उल्लंघन मामलों में आई कमी

नई दिल्ली,6 अप्रैल (ए)। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में बताया है कि विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों की उल्लंघना के मामलों में कमी आई है। 2016 में ऐसे मामलों की संख्या 352 थी, जबकि 2017 में इनकी तादाद घटकर 269 रह गई है। वह लोकसभा में आए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। पेयजल व स्वच्छता मामलों के राज्य मंत्री रमेश चंदप्पा ने लोकसभा में बताया कि 27 फीसद आदिवासियों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। जबकि 75 फीसद लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। 2011 की जनगणना के हवाले से यह बात सदन में बताई गई। उनका कहना था कि इन लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय देने की व्यवस्था की जा रही है। एचआरडी राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में बताया है कि छात्रों की रुचि विज्ञान विषय में बढ़ी है। 2014-15 के दौरान हायर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान लेने वाले छात्रों की तादाद 62.18 लाख थी, जो 2015-16 में बढ़कर 79.52 लाख हो गई। सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लांच किया था। इसका उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना था। सड़क परिवहन मामलों के राज्य मंत्री मनसुख लाल ने लोकसभा में बताया कि सरकार उत्तर-पूर्व में सड़कों के चौड़ीकरण का काम करेगी, जिससे बांग्लादेश व म्यांमार के साथ संपर्क मजबूत किया जा सके। इससे इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

कुंवारापन है मेरी सफलता और खुशी की वजह : रामदेव

पणजी, 6 अप्रैल (ए)। योग गुरू रामदेव ने कहा है कि उनकी सफलता और आनंदपूर्ण जीवन की एक वजह उनका कुंवारा होना है। 52 वर्षीय योग गुरू गोवा महोत्सव, 2018 को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत वीरवार को पणजी के निकट हुई। आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि समूह की स्थापना करने वाले रामदेव ने कहा कि कंपनी का पंजीकरण गैर लाभकारी धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी क्योंकि इसका लक्ष्य धन कमाना नहीं है। उन्होंने कहा लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। न बीवी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। शादी आसान बात नहीं है। कई लोग अभी शादी करेंगे और कई कर चुके हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको जिंदगी भर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है।' ' रामदेव ने कहा, आपको खुश रहने के लिए पत्नी और बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती है।

अमेरिका मैक्सिको सीमा पर तैनात होंगे नेशनल गार्ड

वाशिंगटन,6 अप्रैल (ए)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका- मैक्सिको की सीमा पर नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। इस बाबत उन्होंने संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मैक्सिको से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहा था। यह कार्रवाई उसी तरफ बढ़ाया गया अगला कदम है। हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि रक्षा सचिव जेम्स मैट्रिस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की मांग करेंगे। सीमा की सुरक्षा और जवानों के प्रशिक्षण के लिए वह गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टीन नीलसेन से मिलकर काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने का भी प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट किया था कि दीवार बनने तक सीमा पर सेना तैनात रहेगी। नीलसेन ने इस पर कहा कि यह केवल अमेरिकी समुदाय और बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कानून के नियमों के लिए भी खतरा है। यह कार्रवाई का समय है। सीमा पार से लगातार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, खतरनाक गिरोहों की आवाजाही हो रही है। यहां से अंतरराष्ट्रीय अवैध आव्रजन भी हो रहा है। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक सीमा गश्ती दल हर रोज एक हजार अवैध लोगों को सीमा पार करते गिरफ्तार कर रहा है। हालांकि नेशनल गार्ड वहां पर क्या काम करेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी और कब तक तैनात किए जाएंगे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। बुश प्रशासन के समय सीमा पर नेशनल गार्ड की तैनाती पर 41.5 करोड़ डॉलर का खर्च आया था।

दारोगा का इस्तीफा : कहा इस सिस्टम से मेरी आस्था पूरी तरह टूट चुकी

बाराबंकी, 6 अप्रैल (ए)। कोठी थाने में तैनात दारोगा अनिल द्विवेदी ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक वीपी श्रीवास्तव को अपना इस्तीफा थमा दिया। इस्तीफा देख एसपी चौंक गए और समस्या का निराकरण करने का आश्वासन देते हुए उसे शांत कर लौटा दिया। दारोगा ने एसपी को इस्तीफा देकर कहा है कि इस सिस्टम से मेरी आस्था पूरी तरह टूट चुकी है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी वीपी श्रीवास्तव ने कहा कि उपनिरीक्षक की समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। उसने जो इस्तीफा दिया था उसे वापस ले लिया है। अब ऐसा कोई मामला नहीं है।

बड़ों के रहे बड़े-बड़े काम : दरअसल, कोठी थाने में तैनात उपनिरीक्षक अनिल द्विवेदी थाने में दर्ज अपराध संख्या 41/18 के विवेचक थे। थाना क्षेत्र के ग्राम टिकैतनपुरवा निवासी अरुण कुमार मिश्रा की पत्नी रेनू मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पुत्र अभिषेक पर रिश्तेदार राहुल मिश्रा ने ब्लेड से हमला किया है। विवेचना में आरोप असत्य पाए जाने पर उपनिरीक्षक अनिल ने मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों

को प्रेषित कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने भी अपनी जांच में आरोप फर्जी बताए। इसी बीच रेनू मिश्रा पक्ष से दारोगा पर पांच लाख रुपये लेकर गलत कार्रवाई का आरोप लगा। जिस पर मामले की जांच एएसपी दक्षिणी से कराई गई। एएसपी दक्षिणी शशिकांत तिवारी ने विवेचक के खिलाफ रिपोर्ट दे दी। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उसे लाइन हाजिर कर दिया। इस कार्रवाई से आहत होकर गुरुवार की सुबह दारोगा अनिल द्विवेदी एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी वीपी श्रीवास्तव के समक्ष पेश हुए और अपने हाथ से लिखा हुआ दो पन्नों का इस्तीफा सौंप दिया।

इस्तीफे में लिखा-थक गया हूं, हारा नहीं : इस सिस्टम से मेरी आस्था और मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। मैं एक छोटा सा कर्मचारी करोड़पति अरुण मिश्रा के लालच व भय में नहीं आया और न किसी दबाव में आया, लेकिन आज मैं पूरी तरह से थक गया हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। अधिकारी कह रहे हैं कि अरुण मिश्रा का दबाव आ रहा है, ये कहो कि सस्पेंड नहीं हुए लाइन हाजिर हुए हो। इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईमानदारी से काम करने का परिणाम यही होता है। महोदय प्रार्थी उक्त बातों से व्यथित होकर अपना इस्तीफा आपको दे रहा है स्वीकार करने की कृपा की जाए।

कौन है अरुण मिश्रा : जिसके दबाव में दारोगा पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, बताया जाता है कि वह अरुण मिश्रा दिल्ली में किसी आइएएस अधिकारी का ड्राइवर है। राहुल मिश्रा उनके सगे रिश्तेदार हैं, जिनमें जमीन का विवाद है और परेशान करने की नीयत से मुकदमा दर्ज कराया था। भुक्तभोगी दारोगा का कहना है कि उसने निष्पक्ष होकर जांच व कार्रवाई की। जिसके बदले में अरुण मिश्रा ने मुझे फोन पर गालियां सुनाई और मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई कर दी गई, जिससे वह बहुत आहत है।

किराये के मकान में रहता हूं : प्रतादना से आजिज दारोगा अनिल द्विवेदी की मनोदशा इस कदर प्रभावित हुई है कि फोन पर बात करते हुए वह रो पड़ा। कहा, क्या सत्यपथ पर चलने वालों का कोई साथ नहीं देता। यकीन किसी को हो या न हो, यह सच है कि दारोगा की नौकरी के बाद भी किराए के मकान में परिवार रहता है, पुरानी मोटरसाइकिल से चलता हूं, हर रोज मेरी धर्मपत्नी ड्यूटी पर जाते समय यही कहती हैं, कि कुछ भी करना किसी बेगुनाह को न सताना, क्योंकि इसका असर बच्चों पर आया तो, कभी आपको माफ नहीं करूंगी। शायद यही पारिवारिक संस्कारों का बंधन है, जो अब सत्यपथ से डिगने नहीं देता। कोई ताकत अब मेरे फैसले से डिगा नहीं सकती, जबतक न्याय नहीं मिल जाता। यह वेदना अनिल ने बातचीत के दौरान कही। अनिल मीडिया में अपना कोई पक्ष नहीं देना चाहते।

चार गांवों तक पहुंचने के लिए एकमात्र लकड़ी के पुल की हालत खराब, सरकार से मरम्मत की अपील

साम्बा, 6 अप्रैल (ए)। एक तरफ केंद्र सरकार देश को डीजिटल बनाने के लिए पूरे काम कर रही है और नई-नई स्कीमें लांच कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिला साम्बा के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अधुनिक सुविधाओं से तो दूर 5 दशक पूराने बनाए गए पुलों की मरम्मत को तरस रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि देश का विकास तभी संभव होगा, जब इन लोगों तक लगातार विकास की किरण पहुंचेगी। साम्बा जिला के कारड पंचायत के गांव प्यूर में बने हुए लकड़ी के पुल की हालत भी इन दिनों पूरी तरह से दयानीय हो रही है। बसंतर के उपर बने इस पुल में हर समय किसी के गिरने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसकी रेड्क्षलग पूरी तरह से टूट गई है और इस समय उसे मरम्मत की बहुत अधिक जरूरत है। प्यूर के इस पुल से होकर ही लोग कारड, लेयान बगूल, सैल कोडी बैर और कारड तक पहुंचते हैं, जबकि इन दिनों पहाड़ी गांवों के बक्करबाल अपने माल मवेशी लेकर बड़ी संख्या में कश्मीर की तरफ जा रहा है तो इसी शार्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक दशक से मरम्म को तरस रहे पुल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पांच दशक पहले बनाया गया था पुल : जानकारी अनुसार इस पुल का निमार्ण 5 दशक पहले किया गया था और उस समय यह पुल अपने-आप में एक मिसाल बनी थी, क्योंकि बसंतर के उपर लोगों को राहत दिलाने के लिए एक यह बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद बीच-बीच- में इसकी मरम्मत होती गई, लेकिन पिछले एक दशक से कुछ भी नहीं किया जा रहा। कारड पंचायत के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह नीटू ने कहा कि कई बार प्रशासन तक उन्होंने अपनी मांग को पहुंचाया, लेकिन ऐसा अंदेशा लग रहा है कि प्रशासन व सरकार किसी बड़े हादसे के होने के बाद ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी।

टीडीपी सांसदों ने राज्यसभा स्थगित होने के बाद भी उच्च सदन में जारी रखा धरना

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (ए)। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज राज्यसभा स्थगित होने के बाद उच्च सदन और संसद के केन्द्रीय कक्ष में धरने पर बैठ गये। धरना पर बैठे कुछ सांसदों की तबीयत भी बिगड़ गयी। राज्यसभा सदस्य सी एम रमेश ने बताया कि उच्च सदन की बैठक आज अपराह्न दो बजकर करीब 35 मिनट पर स्थगित होने के बाद से ही उनकी पार्टी के सदस्य सदन से बाहर नहीं गये। पार्टी सदस्य सदन में ही धरना देकर बैठ गये। उन्होंने बताया कि उपसभापति पी जे कुरियन बीच में पार्टी सांसदों से बात करने के लिए आए थे।

रमेश ने बताया कि बीच में उनकी और पार्टी की अन्य सांसद टी सीताराम लक्ष्मी की तबीयत कुछ खराब हुई। सदन में ही की गयी चिकित्सकीय जांच में इन दोनों के रक्तचाप में कमी पायी गयी। तेदेपा नेता राममोहन नायडू ने बताया कि पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के समर्थन में तेदेपा के 15 लोकसभा सदस्य संसद के केन्द्रीय कक्ष में धरने पर बैठ गये। उन्होंने बताया कि सांसद अवंति श्रीनिवास राव का रक्तचाप बढ़ने के कारण उन्हें राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया है। रमेश ने बताया कि राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा सदन में आये थे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे सदन में ही धरने पर बैठे रहेंगे।

लालू प्रसाद यादव बोले, देश में अघोषित आपातकाल की है स्थिति

पटना, 6 अप्रैल (ए)।राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है और आजादी के 70 सालों में दबे कुचले और उपेक्षित वर्ग ने इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। पटना में आज राजद विधायकों की बैठक के दौरान करोड़ों रूपये के चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू के पढ़े गए उक्त संदेश में कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्ग राजद से आस लगाए बैठे हैं कि हम उनकी वेदना को पूरी ताकत से हर मंच पर उठाएं और उनकी आवाज को बुलंद करें।

लालू ने आगे कहा है कि आजादी के 70 सालों में दबे कुचले और उपेक्षित वर्ग ने इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा । यह अघोषित आपातकाल का दौर आपातकाल से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि आज संविधान को बदलने की बात ही धड़ल्ले से की जा रही है। राजद प्रमुख जो कि वर्तमान में दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं, ने अपने संदेश में आरोप लगाया है कि कमजोर वर्ग की रक्षा करने वाले कानून को हटाया और बदला जा रहा है।

सरकार के विरूद्ध आवाज उठाने को देशद्रोह का नाम दिया जा रहा है। स्वयं केंद्र सरकार की ओर से उन ताकतों को बल दिया जा रहा है जो समाज को बांटने, समाज का ध्रुवीकरण करने और ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतने को अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ दबे कुचले, उत्पीडित, उपेक्षित, शोषित और वंचित वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी आज राजद से उम्मीद करते हैं कि हम फिरकापरस्त और मनुवादी ताकतों को ललकारें और उन्हें पराजित भी करें । लालू ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन हमें अपने संघर्ष का स्मृति चिन्ह बनाकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की ओर आगे बढना है तथा उस दिन दलित बस्तियों और कमजोर वर्ग के बीच जाकर उन्हें न केवल प्रताड़ित होने से बचाएं बल्कि उन्हें केंद्र और दक्षिणपंथी संगठनों के जन और समाज विरोधी हथकंडों और दुष्प्रचार से भी अवगत कराएं।

2.41 लाख करोड़ के लोन को वेव व राइट ऑफ पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (ए)। बैंक लोन को राइट ऑफ व वेव ऑफ के बीच में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी फंस गई है। जिससे यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी को बैंकों द्वारा लोन की रकम राइट ऑफ करने और वेव ऑफ किए जाने का अंतर पता नहीं है क्योंकि सरकार ने जब स्वीकार किया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2.41 लाख करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि सरकार ने उद्योगपतियों का 2.41 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। हालांकि, लोग इसे मोदी सरकार को बदनाम करने की सोची-समझी चाल मान रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी का दावा : राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि 2014 से सितंबर 2017 के बीच सरकारी बैंकों ने कारोबारी प्रतिष्ठानों को दिए 2.41 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ (वेव ऑफ) कर दिया। कांग्रेस ने इसे 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से जोड़ दिया। पार्टी ने पूछा, क्या शायद यह तब नए-नए पीएम बने नरेंद्र मोदी की ओर से अपने कारोबारी मित्रों को त्वरित धन्यवाद ज्ञापन था

यह है हकीकत : दरअसल, रीतब्रत बनर्जी के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 के बीच 2,41,911 करोड़ रुपये का लोन राइट ऑफ किया है। इसकी जानकारी देते हुए स्पष्ट बताया गया कि नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स (फंसे लोन) का राइटिंग ऑफ करना (बट्टा खाता में डालना) एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे बैंक अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए अपनाते हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने अपने लिखित जवाब में बताया, टैक्स बेनिफिट और कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर्जों एवं संबंधित मदों की रकम बट्टा खाते में डाली जाती है। ये लोन लेनेवालों पर कर्ज चुकाने का दायित्व बरकरार रहता है, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बकाया वसूली लगातार चलती रहती है। जवाब में कहा गया है, इसलिए राइट-ऑफ से कर्जदारों को फायदा नहीं पहुंचता है। इस लिखित जवाब के आखिरी पैरे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 45श्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन कॉर्पोरेट्स के लोन राइट ऑफ किए गए, उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने अपने आर्टिकल को ट्वीटर पर ट्वीट भी किया है। इस पर कई लोग इसे कांग्रेस की साजिश के रूप में भी देख रहे हैं। सुनील जैन ने लिखा, राहुल गांधी, यह वाकई अविश्वसनीय है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को तथ्यों को इस हद तक तोड़ना-मरोड़ना चाहिए। लोन के राइटिंग ऑफ और इसके वेविंग ऑफ में अंतर है।

क्या होता है राइट ऑफ : जब किसी लोन की ईएमआई बैंक को नहीं मिलती है, तो उसका राजस्व घटने लगता है क्योंकि तब उसे उस लोन पर ब्याज नहीं मिल रहा होता है।

मेरे आंदोलन को आरएसएस के साथ जोड़कर छवि खराब करने की चल रही है कोशिश : हजारे

अहमदनगर, 6 अप्रैल (ए)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दावा किया कि, निहित स्वार्थ वाले लोग मुझे और लोकपाल के लिए पिछले महीने दिल्ली में किए गए मेरे आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जोड़कर मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारे ने29 मार्च को केंद्र के इस आश्वासन के बाद रामलीला मैदान में अपना छह दिवसीय भूख हड़ताल खत्म किया था कि किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य मिलेगा और लोकपाल की नियुक्ति होगी तथा चुनाव सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'इस तरह के निराधार आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से एक गिरोह काम कर रहा है।' उन्होंने कहा, 'निहित स्वार्थ वाले लोग मेरी और मेरे आंदोलन की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।' कार्यकर्ता कल्पना इनामदार को नाथूराम विनायक गोडसे से जोड़े जाने की खबरों को हजारे ने खारिज किया। दिल्ली में23 मार्च के आंदोलन से पहले उन्हें20 सदस्यीय राष्ट्रीय कोर समिति में शामिल किया गया था। हजारे ने बयान जारी कर कहा, 'इनामदार को गोडसे से एक षड्यंत्र के तहत जोड़ा गया ताकि मेरे नेतृत्व वाले आंदोलन को बदनाम किया जा सके।

पापुआ हिंसा में एक की मौत, डरे-सहमे गांव वाले जंगलों में छिपने को मजबूर

जकार्ता, 6 अप्रैल। इंडोनेशियाइ सैन्यकर्मियों (टीएनआइ) और पापुआ में सिनाइ ओपिटवाक चर्च के स्थानीय सशस्त्र समूह के बीच हाल में हुए संघर्ष का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। इस संघर्ष के कारण सैकड़ों गांववाले पास के जंगलों में छिपने के लिए मजबूर हैं। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि तीन ग्रामवासी (पईशनर) घायल हो गए हैं। बुधवार को सुबह आठ बजे टीएनआइ और राष्ट्रीय पुलिसकर्मियों द्वारा मारे गए छापे में ग्रामवासी (पईशनर) टिमोटियस उमाबक को गोली मार दी गई थी। बुधवार दोपहर को उसे ओपिटवाक में दफनाया गया था। सिनाई ओपिटवाक चर्च के पादसी देसीरियस आदी ने कहा टिमोटियस अन्य ग्रामवासियों के साथ चर्च के बरामदे के सामने खड़ा था, जब फायरिंग हो रही थी। गुरुवार को फोन पर जकार्ता पोस्ट को दिए इंटरव्यू में देसीरियस ने कहा, वे सभी लाल और सफेद राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे और उन्होंने सेनाकर्मियों को दिखाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे, ये बताने के लिए कि वे सशस्त्र समूह से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन उन्होंने गोली चला दी। देसीरियस ने कहा, वे अब भी नहीं जानते कि बाकी के कुछ लोगों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वे सेना से छिपने की कोशिश में जुटे थे। मैं कल रात से उनमें से किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। इस शूट आउट के जवाब में इंडोनेशियाई कम्यूनियम ऑफ चर्च (पीजीआइ) के सेक्रेटरी जनरल गोमर गुल्टोम ने कहा कि कम्यूनियम अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इसके साथ ही उन्होंने पापुआ के मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य बल के बजाय एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए सशस्त्र बलों से आग्रह किया है। उन्होंने पापुआ में सैन्य और सशस्त्र समूहों से आग्रह किया है कि नागरिकों पर अपनी शत्रुताएं न निकालें।

यहां कंपनी का बॉस बताता है कब होना है प्रेगनेंट बिना इजाजत मां बनी तो चली जाएगी नौकरी!

कनाडा, 6 अप्रैल। किसी भी औरत के लिए मां बनना बेहद सुखद अनुभूव होता है। दुनिया की हर महिला गर्भवती होने या मां बनने पर गर्व की अनुभूति महसूस करती हैं।लेकिन जापान में एक महिला को गर्भवती होने पर बॉस की डांट सूननी पड़ रही है। दरअसल, वह महिला अपनी बारी आने से पहले यानी आउट ऑफ टर्न प्रेगनेंट हो गई हैं। इस वजह से उसे बॉस की कई बातें सूननी पड़ रही है। इस बात का खुलासा उनके पति ने ही किया है । उन्होंने बताया, मेरी पत्नी चाइल्ड केयर सेंटर पर काम करती है। बॉस ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं कि प्रेगनेंट होने के लिए कंपनी के नियम तोड़ दें

इस कंपनी के नियमों के मुताबिक किसी भी महिला कर्मचारी को शादी करने या प्रेगनेंट होने के लिए बॉस की इजाजत लेनी होगी। इसमें भी एक अघोषित नियम है कि जूनियर सदस्य स्टाफ के सीनियर सदस्य से पहले शादी नहीं करेंगी या प्रेगनेंट नहीं होंगी। अब मेरी पत्नी को आउट ऑफ टर्न प्रेगनेंट होने के लिए परेशान किया जा रहा है। अगर कोई महिला कंपनी के नियमों के मुताबिक अपनी बारी आने से पहले ही शादी कर लेती हैं या प्रेगनेंट हो जाती हैं, तो उसे स्वार्थी कदम माना जाता है।

इतना ही नहीं टोक्यो के मिताका में एक कॉस्मेटिक कंपनी ने भी कुछ ऐसे ही आदेश कर्मचारियों को दिए हैं। 26 वर्षीय युवती ने बताया, मुझे और 22 अन्य महिला कर्मचारियों को कंपनी ने एक ई-मेल भेजा। इसमें शादी और बच्चे को लेकर मैपिंग की गई थी। इसमें सभी को उम्र के हिसाब से बताया गया था कि किसे कब शादी करनी है और कब प्रेगनेंट होना है। इतना ही नहीं, एक मामले में तो महिला कर्मचारी को बॉस ने ये कह दिया था कि उसे 35 साल की उम्र से पहले प्रेगनेंट नहीं होना है।